

सम्पादकीय

नवानन्माण का मत्र आत्मानभरता
त के नीति-निर्माताओं के लिए आत्मनिर्भरता कोई नया शब्द नहीं

नारत के नाता—नानाताजो के लिए आनन्दनरा को इन्होंने शब्द नहीं हासा आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में योजनागत विकास के नाम पर जो नीति बनी, उसे भी आत्मनिर्भर भारत कहा गया था, लेकिन जो कार्यनीति अपनायी गयी, जिसे अर्थशास्त्री महालनोबिस कार्यनीति के नाम से पुकारते हैं, उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े और मूलभूत उद्योगों की स्थापना, बड़े बांधों के निर्माण समेत देश को एक मजबूत औद्योगिक ढांचा देने की बात कही गयी थी। इसे आत्मनिर्भरता की कार्यनीति कहा गया, प्रारंभिक रूप से इसके कारण विदेशों पर निर्भरता इतनी बढ़ गयी कि 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद हमें तीन वर्षों तक योजना की छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि योजना को कार्यान्वित करने के लिए जरूरी आर्थिक संसाधन देश के पास नहीं थे। देश में औद्योगीकरण की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपी गयी और कहा गया कि विकास का एकमात्र यही सही रास्ता है तथा निजी क्षेत्र या निजी उद्यमिता के माध्यम से यह इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास न तो संसाधन हैं, न ही जोखिम लेने की क्षमता व इच्छाशक्ति और न ही दीर्घकालीन दृष्टि।

लिए निजा उद्यम का अनुमति ता मिला, लाकन उसम भा लाइसेस व्यवस्था लागू कर दी गयी। इनके लिए कच्चे माल हेतु कोटा व्यवस्था लागू हुई। अधि-
क उत्पादन करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया। स्वाभाविक तौर पर
सरकारी क्षेत्र के दबदबे और निजी क्षेत्र का दम घोटती आर्थिक नीतियों से
कायम व्यवस्था का असर यह हुआ कि देश में जो भी उत्पादन होता था, वह
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पधात्मक नहीं होता था। इसका कारण था कि
निजी क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी विकास, नये मॉडल बनाने और कुशलता बढ़ाने
के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। ऐसे में संभव था कि लोग अच्छे उत्पाद सरके
दामों पर विदेशों से आयात कर लें। तब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा
उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार बाधित हो जाता। इस संभावना को समाप्त
करने के लिए विदेशी वस्तुओं के आयात पर कई तरह की रोक जरूरी थी।
एक ओर अनेक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसे मात्रात्मक
नियंत्रण कहते हैं, तो दूसरी ओर जिन वस्तुओं के लिए आयात की अनुमति
थी, उन पर बहुत आयात शुल्क लगाया गया, ताकि लोग आयात से हतोत्साहित
हो जाएं। चूंकि आयात नियंत्रित हो गया, तो देश में विदेशी मुद्रा की मांग भी
नियंत्रित हो गयी। ऐसे में सरकार आसानी से विनिमय दर का अपनी मर्जी के
अनुसार तय कर सकती थी। वर्ष 1964 तक डॉलर की विनिमय दर केवल
4।16 रुपये प्रति डॉलर थी, 1966 और 1967 में रुपये का मूल्य द्वास क्रमशः
6।36 और 7।50 रुपये प्रति डॉलर तक हो गया।

हफ्ते चीनी निर्मित हंबनटोटा बंदरगाह पर चीनी जासूस जहाज युआनवामग-५ को डॉक करने के श्रीलंका के फैसले के बारे में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के देर से दिए गए बयान में कि चीन को सैन्य उद्देश्यों के लिए बंदरगाह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भारत की चिंता को अस्थायी रूप से कम करने का इरादा हो सकता है। इस तरह के वादे का कोई कानूनी या तार्किक आधार नहीं है। श्रीलंका के गहरे समुद्र में हंबनटोटा बंदरगाह, जिसे चीन ने अपने वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम (बीआरआई) के हिस्से के रूप में एक अरब डॉलर से अधिक की लागत से बनाया है, तकनीकी क्षमते



लागत से बनाया है, तकनीकों रूप से चीन का है। 2017 में एक समझौते के तहत, श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी ने हंबनटोटा इंटरनेशनल पोर्टगुप (एचआईपीजी) बनाया, जो चीन के मर्चेंट पोर्ट्स द्वारा एचआईपीजी में 85 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के बाद चीनी कंपनी के 1.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की सुविधा के लिए एक संयुक्त उद्यम बन गया। इस प्रकार, एचआईपीजी बहुसंख्यक चीनी स्वामित्व में है। चीन बंदरगाह का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता है। भविष्य में हंबनटोटा में ऐसे और चीनी युद्धपोतों के डॉक करने की उम्मीद है। इसी तरह, चीन ने चटगांव और पायराडीपसी पोर्ट परियोजनाओं में बांग्लादेश में बड़े रणनीतिक निवेश किए हैं। चीन कुछ अरब डॉलर की अनुमानित लागत वाली पेराडीपसी पोर्ट परियोजना का वित्तपोषण और निर्माण कर रहा है। बंदरगाह बांग्लादेश में तीसरा सबसे

सांस चान आर बांग्लादेश के बाच न शताँ पर आधारित है। दोनों ने इसंयुक्तआर्थिक विकासश के एक पारस्परिक समझौते पर क्षर किए। चीन ने पेराडीप-सीपोर्ट वेस्टराओर विकास में विशेष रुचि दो चीनी फर्मों-चाइना हार्बर नियरिंग कंपनी और चाइना स्टेट इक्वशन इंजीनियरिंग कंपनी- ने गाह के मुख्य बुनियादी ढांचे और रियन पहलुओं के विकास के लिए मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे, जिसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा दि के लिए सेवाएं शामिल हैं। यह ने का कोई कारण नहीं है कि अपने युद्धपोतों को लंगर डालने लिए इन बंदरगाहों का उपयोग न कर्ता। कई लोगों का मानना है कि लादेश में दो बड़ी बंदरगाह योजनाओं को विकसित करने में की रुचि के पीछे अंततरु उन संप्रभु नियंत्रण का प्रयोग करना है बांग्लादेश न चटगांव में पाकिस्तानी नौसेना के लिए चीन निर्मित युद्धपोत के डॉकिंग की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बांग्लादेश भविष्य में चीन के अपने युद्धपोतों पर भी ऐसा ही रुख अपनाएगा। ढाका में, अधिकारियों को सावधान कहा जाता है कि चीन द्वारा चटगांव और पायरा बंदरगाहों पर अद्वितीय नियंत्रण शुरू करने में अधिक समय नहीं लग सकता है। बांग्लादेश जल्द ही चीन के कर्ज परिवर्तन के प्रयास का शिकार हो सकता है। चीन बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब लाने की कोशिश कर रहा है, जहां वह ग्वादर में एक बंदरगाह परिसर का निर्माण कर रहा है, जिससे बांग्लादेश को मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार करने में आसानी होगी। चीन के बहु-अरब डॉलर के ग्वादर बंदरगाह परिसर, जिसे पोर्ट-पार्क-सिटी के रूप में बिल किया जा रहा है, एक बड़ी बांग्लादेशी नियंत्रण का विकास करना है।

बंगलादेश की बौखलाहट

लेस के हरस्स के रूप में देखा जाता है जो चीनी सेना के नेटवर्क को संदर्भित करता है और संचार की समुद्री लाइनों के साथ वाणिज्यिक सुविधाएं और संबंध –चीन की मुख्य भूमि से पोर्ट सूडान, अफ्रीका के हॉर्न तक। समुद्र की रेखा इंडियन प्रमुख समुद्री चौक पॉइंट्स जैसे पांडेब, मलकका, होम्पुज और लोब्होक के जलडमरु मध्य से होकर गुजरती हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अलदीव और सोमालिया में अन्य एशियनीक समुद्री केंद्रों के रूप में। ग्वादर बंदरगाह को सीपीईसी (चीन पाकिस्तान आर्थिक गतियारा) परियोजनाओं की प्रमुख सफलताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया है। आलोचक ग्वादर बंदरगाह परिसर को किस हिस्से के रूप में देखते हैं चीन की शकर्ज-जालश नीति में अरबों डॉलर के सॉफ्टलोन, एक पाकिस्तानी शहर में चीनी एन्क्लेव की व्यापना और एक ग्रेकानूनी क्षेत्र में

कर रहा था तो उसे बुझा करना
टोटा के मामले में, ग्वादर की
मास्टर्स इस्लामाबाद नहीं
गया में बैठते हैं। कागज पर, चीन
चतुर्भुजश सहयोग का उद्देश्य
देश और श्रीलंका को पाकिस्तान
रीब लाना और उन्हें ग्वादर
गाह का उपयोग करने के लिए
करना है ताकि वे चाय और
ड कपड़ों जैसे अपने माल का
करने के लिए मध्य एशियाई
ज्यों तक पहुंच सकें। हालांकि,
का अंतिम उद्देश्य हिंद महासागर
में अपनी मजबूत नौसैनिक
थति स्थापित करने के लिए लिंक
उपयोग करना प्रतीत होता है।
ही में अमेरिकी रक्षा विभाग
(न) की एक रिपोर्टमें कहा गया
वां चीन के पास लगभग 355
तों और गिनती के साथ दुनिया
बसे बड़ा समुद्री बल है। पीपुल्स
शन आर्मीनेवी अगले चार वर्षों
के नारे जिनका इप्रोग पर 420 जहाजों
तक विस्तारित करने के लिए तैयार
है। विशाल बैडे में प्रमुख सतही लड़ाके,
पनडुब्बियां, विमानवाहक, समुद्र में जाने
वाले उभयचर जहाज, खान युद्धक
जहाज और बैडे सहायक शामिल हैं।
इस आंकड़े में 85 गश्ती लड़ाके और
शिल्प शामिल नहीं हैं जो जहाज—रोड
पि क्रूज ले जाते हैं। बीजिंग की विदेशी
उपस्थिति का समर्थन करने के लिए
सुविधाओं की तलाश कर रहा है।
बांगलादेश में गहरे बंदरगाहों के निर्माण
और पुनर्गठन में चीन की दिलचस्पी
का उद्देश्य थाईलैंड, म्यांमार, बांगलादेश,
श्रीलंका, पाकिस्तान और ईरान के क्षेत्र
को नियंत्रित करना है। चीन की
दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा
प्राथमिकताओं में से एक यह है कि
वह अपने विदेशी हितों के साथ—साथ
संचार की अपनी वैशिक समुद्री लाइनों
की सुरक्षा को बनाए रखने में सक्षम
हो। — नंतु बनर्जी

तुला :- समय के संकरके चलने का प्रयास को ही अपनी पजा से

ये उत्साह का सचार होगा। आमाजिक गतिविधियों में क्रियाशीलता ढेगी। भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंध मधुरत होंगा।

षष्ठि :- हर घटना से आपको सीखने की जरूरत है। नये क्षेत्र में नेश से पूर्व जानकार लोगों से बेचार-विमर्श करें। भविष्य के पति

का उसा आर काद्रित कर। पत्ना क साथ मधुर वणी का प्रयोग करें। रोजगार में लाभकारी स्थिति रहेगी।

वृश्चक :- स्वयं को सही दिशा और लक्ष्य की ओर केंद्रित करें तभी जीवन में सही प्रगति कर सकते हैं। किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनभित्ति करेंगे। यहाँ की

वृश्चिक :- स्वयं को सही दिशा और लक्ष्य की ओर केंद्रित करें तभी जीवन में सही प्रगति कर सकते हैं। किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभवि करेंगे। यहाँ की

अनुकूलता से अवरोधित कार्य हल होंगे।

व लगन स प्रगति को आर अग्रसर होंगे।

आंतरिक क्षमताओं का एहसास कराएंगी। संतान संबंधी दायित्वों की पूर्ति होगी।

से मान-प्रतीच्छा बढ़गो। राजनीति को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। परिजनों के सुख-दुख के प्रति मन चिंतित होगा।

बढ़ेगा। भौतिक आकाश्वाओं को पूते में व्यय अपेक्षित है।

ने दिनों यहां के मुख्यमन्त्री श्री नीतीश है कि उन्होंने एक बार फिर इस राज्य

दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाउस स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा के तुरंत बाद नेपाल में चीन की राजदूत हो यांकी ने एक वक्तव्य में कहा कि चीन



स अमेरिका, यूरोपाय दश एवं विभन्न अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं ने नेपाल की आलोचना की थी। इन संस्थाओं में एमनेस्टी इंटरनेशनल एवं ह्यूमन राइट्स वॉच भी शामिल थे। नेपाल को लेकर चीन पहले से ही परेशान नजर आता रहा है। इसी वर्ष मिलानयम चालज कारपारशन अमेरिका की एक अनुदान शाखा है, जो जरूरतमंद देशों को विकास कार्यों के लिए बड़ी धनराशि मुहैया कराती है। वर्ष 2017 में अमेरिका ने एमसीसी के तहत नेपाल को पांच सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की

ये गालीबाज लोग, क

एटिव (बीआरआइ) के विरोध में जा रहा था, सो नेपाल की स्टर्ट सरकार एमसीसी के मसले पर ही रही। इतना ही नहीं, एमसीसी अमेरिका की हिंद-प्रशांत नीति पर हिस्सा बताया गया, जिसके नेपाल में उग्र आंदोलन भी हुए। जुलाई, 2021 में कम्युनिस्ट प्रकाशक के गिरते ही नेपाली कांग्रेस और ने एमसीसी के प्रस्ताव को में पारित करा दिया। पिछले हीनों में अमेरिका के कई उच्च अधिकारियों एवं प्रतिनिधि मंडलों ने का दौरा किया है। इससे चीन राहट स्पष्ट दिख रही है। नेपाल ने तेहासिकता 1959 में तिब्बत में आम्पा विद्रोह के संदर्भ में भी जाती है, जिसमें अमेरिका ने के रास्ते तिब्बती विद्रोहियों को पहुंचाया था। दूसरी ओर, भारत नाल के संबंधों में बढ़ती प्रगाढ़ता की लिए चुनौती का सबब

पिछले सात दशकों में भारत ने साफ किया है कि भारत की नेपाल नीति आपसी सहयोग एवं परस्पर विकास की नीति पर आधारित है, जिसका एक बड़ा हिस्सा जनसंपर्क पर स्थिर है। लेकिन भारत-नेपाल संबंधों में आकस्मिक मन-मुठाव से उपजे खालीपन को चीन ने अपने फायदे हेतु उपयोग करना चाहा है। इस परिप्रेक्ष्य में चीन के लिए नेपाल हमेशा से एक मुश्किल कड़ी रहा है। मौजूदा स्थिति में चीन यह जरूर चाहेगा कि नेपाल श्वन चीन नीतिश की प्रतिबद्धता को मजबूत रखे। चीन यह भी जानता है कि व्यापार, निवेश एवं सुरक्षा के लिए नेपाल में एक मैत्रीपूर्ण कम्युनिस्ट सरकार की जरूरत है। ऐसे में चीन 20 नवंबर को नेपाल में होने वाले संसदीय चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टियों के सहयोग या नेतृत्व वाली सरकार की उम्मीद कर रहा है। — **ऋषि गुप्ता**

रतन ताला पानी हरता हुका
र वह मध्य वर्ग कहलाता था।
एक शिक्षा पद्धति से निर्मित यह
उपरहले तो सीमित था परन्तु
जैसे लोगों की जीवन शैली बेहतर
गयी और निम्न वर्ग ने
किसानी छोड़कर शहरों-कसर्बों
ना शुरू किया, इस वर्ग का
होता चला गया। बेहतर शिक्षा
ना के कारण उनकी अच्छी
वेकेका होती है। फलतरु सम्पन्न
होने वाले उनके ब्याह, खुद
करी, ज्यादातर कामकाजी जीवन
एवं मां-बाप की सम्पत्ति मिलने
खुद भी धनपति हो जाते हैं।
यह नीती आर्थिक नीति से निजी क्षेत्र
लबाला हो गया, इसलिये यह
जनता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के
भ्रष्ट, अयोग्य और क्षमताहीन
अपने से ऊपर के वर्ग की कृ
आश्रित ये लोग उसी की तरह
चाहते हैं। इसके लिये आवश्यक
कि वह उसी के अनुरूप व्यवहार
नेचले वर्गों को कामचोर, मक्कार
वाला यह वर्ग अपने से छोटे
रियों के साथ डांट-डपट,
र, गाली-गलौज, कड़ाईपूर्ण
में बातचीत एवं कसकर काम
के सम्बन्धों में विश्वास रखता
नस मैडम का वीडियो वायरल
है उस वर्ग के लोगों का इस
का व्यवहार हम आये दिन
टियों के मुख्य द्वारों पर देख
हैं। गालियाँ इसेशा हैंसियत तय

कर्नाटक के राज्य राज्यों बाटा जारी बोया उत्तराखण्ड(यू) के विलय
किया और लालू की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के विरुद्ध बिहार में समानान्तर
राजनैतिक विमर्श खड़ा किया। क्या अपने राजनैतिक जीवन के अन्तिम दौर में
उनका यह समर्पण कहा जायेगा? यदि ऐसा है तो बिहार को उस जंगल राज
से कैसे बचाया जा सके आदित्य चोपडारू बिहार में जो राजनैतिक शखेलाश
पिछले दिनों यहां के मुख्यमन्त्री श्री नीतीश कुमार ने किया उसकी असलियत
यही है कि उन्होंने एक बार फिर इस राज्य को जंगल राजश के हवाले करने
का निर्णय सिर्फ खुद को पढ़ पर बनाये रखने के लिए किया। अगर ऐसा न होता
तो नीतीश बाबू उन्हीं लालू जी के साथ हाथ न मिलाते जिनकी राजनीति के
विरुद्ध उन्होंने पहले समाजवादी नेता स्व. जार्ज फर्नार्डीज के साथ समता पार्टी
और बाद में उसका जनता दल(यू) में विलय किया और लालू की राष्ट्रीय जनता
दल पार्टी के विरुद्ध बिहार में समानान्तर राजनैतिक विमर्श खड़ा किया। क्या
अपने राजनैतिक जीवन के अन्तिम दौर में उनका यह समर्पण कहा जायेगा?
यदि ऐसा है तो बिहार को उस जंगल राज से कैसे बचाया जा सकता है जो
श्रीमान लालू व उनकी पत्नी शाबड़ी देवी के राज में जंगल राज का पर्याय माना
जाने लगा था। आपराधिक माफिया व राजनैतिक गठजोड़ का बिहार में इतिहास
बहुत पुराना नहीं है। इस सेवान्तिक लड़ाई को विशुद्ध जातिगत व सम्प्रदाय गत
आधार देने में लालू प्रसाद की पार्टी की प्रमुख भूमिका रही जिसका मुकाबला
नीतीश बाबू ने भाजपा के साथ मिल कर बखूबी किया। परन्तु इस लड़ाई में
राज्य की केन्द्रीय राजनैतिक पार्टी कांग्रेस की भूमिका हाँशिये पर खिसकती
चली गई जिसकी वजह से बिहार में जाति युद्ध 90 के दशक तक अपने उग्र व
चरम स्वरूप में पहुंचा। वास्तव में यह बिहार की राजनीति का पतन काल कहा
जायेगा क्योंकि इसमें सिद्धान्तों की जगह व्यक्तियों ने ले ली और उन्होंने
अपने-अपने जातिगत कबीलों के आधार पर बिहार के लोगों को लोकतान्त्रिक
दौर से बाहर लाकर कबायली दौर में पटक दिया। अपराधी माफिया व राजनीतिज्ञों
के गठबन्धन का यह स्वर्णिम काल भी कहा जायेगा। पिछले 2020 के विधानसभा
चुनाव में नीतीश बाबू की पार्टी जनता दल(यू) भाजपा की छोटी बहिन की तरह
उभरी। इसकी असली वजह यह थी कि लगातार पिछले तीन चुनावों से
मुख्यमन्त्री रहते नीतीश बाबू की शासनकाल की खामियाँ उजागर होने लगी थीं
जिन्हें ढांपने का काम देश के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं इन चुनावों में
प्रचार की कमान अपने हाथ में लेकर किया। श्री मोदी ने अपनी देश व्यापी
शासन प्रवीण होने की छवि से नीतीश बाबू की ढलती लोकप्रियता और लचर
होती छवि को संभालने का प्रयास किया जिसमें वह सफल रहे और राज्य में पुनः
भाजपा व जनता दल(यू) की स्पष्टकार नीतीश बाबू को जेन्टल में ही गदित हर्दि।

A collage of three images. The first image on the left is a close-up portrait of a man's face, showing his eyes and forehead. The second image in the middle is a woman wearing a green dress with a patterned sash, standing outdoors with trees in the background. The third image on the right is a woman wearing a red sari with a white border, also standing outdoors.



कर ला गया— यह सबका दग कर आता है जन्मने अधिनक युग व श्रेष्ठतम तत्त्वों में से स्वतंत्रता, लोकतंत्र उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास को तो अपना लिया लेकिन मध्य युग का श्रेष्ठता का भाव, जाति-आधारित गैर बराबरी, अहंकार, प्रान्तवाद जैसे तत्त्वों को भी सीने से छिपाया हुआ है। इस वर्ग ने मूलतरु खुद का जन साधारण के सरोकारों से नर्थ आर्थिक नीति के आगमन से ही काटा लिया, जिसका पदार्पण भारत में 90 के दशक की शुरुआत में हुआ था उद्योगों व कारोबारों के विस्तार त नवीनीकरण ने पढ़े-लिखे लोगों का नूतन अवसर दिये जिसका फायद इस वर्ग ने भरपूर उठाया और भारत

क पास चिंता करने का काइ वक्त
नहीं रहता। फेट्हाली के लिये वे गरीबों
को ही जिम्मेदार मानते हैं और एक
हद तक उनका यह भी मानना है कि
अपने हाल के लिये वे खुद जिम्मेदार
हैं। उम्दा शिक्षा, बढ़िया नौकरी, अच्छा
बैंक बैलेंस, मोटर-घर, फेवरेट
डेरिटनेशन्स के नियमित पर्यटन, पांच
सितारा होटलों की पार्टियों में रमा
हुआ यह समाज अब कोढ़ बन चुका है
जो अपने ही देश के उन अधिसंच्चय
नागरिकों से नफरत करता है, जो
उसके मुकाबले आर्थिक या सामाजिक
दृष्टिकोण से बेचारे निचले पायदान
पर हैं। पूँजीकरण एवं ब्रेडब विकास से
दिर्घि दूर वार्ष के न्योर्स के लिये जी

